



## मध्याह्न भोजन व्यवस्था का बच्चों की शिक्षा

### एवं स्वास्थ्य पर प्रभाव : एक अध्ययन

डॉ. रेखा सोलंकी

असिस्टेंट प्रोफेसर (विभागाध्यक्ष)

गृहविज्ञान विभाग

डॉ. मनीष कुमार सैनी

असिस्टेंट प्रोफेसर

समाजशास्त्र विभाग

शासकीय स्नातकोत्तर (अग्रणी) महाविद्यालय

श्योपुर, मध्यप्रदेश, भारत

#### शोध संक्षेप

इस अध्ययन के अन्तर्गत मध्याह्न भोजन व्यवस्था का बच्चों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर प्रभाव के विषय में चर्चा की गई है। इस शोध पत्र में पाया गया है कि इस योजना से स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति और शैक्षिक प्रदर्शन में वृद्धि के साथ-साथ उनके स्वास्थ्य और विकास को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, क्योंकि वर्तमान समय में मध्याह्न भोजन योजना न केवल बच्चों की शैक्षिक उपलब्धियों को बढ़ावा देती है, बल्कि उनके स्वास्थ्य में भी सकारात्मक परिवर्तन लाती है, जिससे उनका समय विकास सुनिश्चित होता है। मध्याह्न भोजन योजना (मिड-डे मील योजना) ने देश भर में प्राथमिक कक्षाओं में लाखों बच्चों को भोजन उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जिससे उनकी पोषण स्थिति और स्कूल में उपस्थिति में उल्लेखनीय सुधार किया है। कहने का तात्पर्य है कि कुल मिलाकर मिड-डे मील योजना ने आवश्यक पोषण प्रदान करके, स्कूल में उपस्थिति को बढ़ावा देकर, सीखने के परिणामों में सुधार करके, वित्तीय बोझ को कम करके और सामाजिक समानता को बढ़ावा देकर गरीब छात्रों और उनके परिवारों पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। यह आर्थिक रूप से वंचित छात्रों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने और उनके समय विकास को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

मुख्य शब्द : स्वास्थ्य, शिक्षा, मध्याह्न भोजन, सरकारी एवं गैरसरकारी, निर्धन परिवार और समाज

#### भूमिका

मध्याह्न भोजन योजना भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय के तहत) की एक योजना है। जिसके अन्तर्गत पूरे देश के प्राथमिक और लघु माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों को दोपहर का भोजन निःशुल्क प्रदान किया जाता है। नामांकन बढ़ाने, प्रतिधारण और उपस्थिति तथा इसके

साथ-साथ बच्चों में पौषणिक स्तर में सुधार करने के उद्देश्य से मध्याह्न भोजन स्कीम देश के 2408 ब्लॉकों में एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में 15 अगस्त, 1995 को आरंभ की गई थी। वर्ष 1997-98 तक यह कार्यक्रम देश के सभी ब्लॉकों में आरंभ कर दिया गया।



वही वर्ष 2003 में इसका विस्तार शिक्षा गारंटी केन्द्रों और वैकल्पिक व नवाचारी शिक्षा केन्द्रों में पढ़ने वाले बच्चों तक कर दिया गया। अक्टूबर, 2007 से इसका देश के शैक्षणिक रूप से पिछड़े 3479 ब्लॉकों में कक्षा 6 से 8 में पढ़ने वाले बच्चों तक विस्तार कर दिया गया है। वर्ष 2008-09 से यह कार्यक्रम देश के सभी क्षेत्रों में उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ने वाले सभी बच्चों के लिए कर दिया गया है। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना विद्यालयों को भी प्रारंभिक स्तर पर मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत दिनांक 01/04/2010 से शामिल किया गया है।<sup>1</sup>

जिसमें अधिकतर बच्चे खाली पेट स्कूल पहुँचते हैं, जो बच्चे स्कूल आने से पहले भोजन करते हैं, उन्हें भी दोपहर तक भूख लग जाती है और वे अपना ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित नहीं कर पाते हैं। मध्याह्न भोजन बच्चों के लिए 'पूरक पोषण' के स्रोत और उनके स्वस्थ विकास के रूप में भी कार्य कर सकता है। यह समतावादी मूल्यों के प्रसार में भी सहायता कर सकता है, क्योंकि कक्षा में विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि वाले बच्चे साथ में बैठते हैं और साथ-साथ खाना खाते हैं। विशेष रूप से मध्याह्न भोजन स्कूल में बच्चों के मध्य जाति व वर्ग के अवरोध को मिटाने में सहायक हो सकता है। स्कूल की भागीदारी में लैंगिक अंतराल को भी यह कार्यक्रम कम कर सकता है, क्योंकि यह बालिकाओं को स्कूल जाने से रोकने वाले अवरोधों को समाप्त करने में भी सहायता करता है। मध्याह्न भोजन स्कीम छात्रों के ज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक विकास में सहायता करता है। सुनियोजित मध्याह्न भोजन को बच्चों में विभिन्न अच्छी आदतें डालने के अवसर के रूप में उपयोग में लाया जा

सकता है। यह स्कीम महिलाओं को रोजगार के उपयोगी स्रोत भी प्रदान करती है।<sup>2</sup>

यह प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये विश्व का सबसे बड़ा विद्यालय भोजन कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के तहत विद्यालय में नामांकित 1 से 8 तक की कक्षाओं में अध्ययन करने वाले 6-14 वर्ष की आयु के हर बच्चे को पका हुआ भोजन प्रदान किया जाता है। मध्याह्न भोजन योजना का नाम 29 सितम्बर, 2021 में बदलकर 'प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण' योजना (पीएम पोषण योजना) कर दिया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नाम बदलने की घोषणा की। पीएम पोषण योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है और इसमें पूर्व-प्राथमिक कक्षाओं के बालवाटिका (3-5 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे) के छात्र भी शामिल हैं। यह योजना सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराती है।<sup>3</sup> योजना का नाम बदलना पोषण पर ध्यान केंद्रित करने के सरकार के प्रयासों का हिस्सा है। पीएम पोषण योजना बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने और भोजन तैयार करने और वितरण की गुणवत्ता में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित करेगी। यह योजना बच्चों की पोषण स्थिति की निगरानी और उनकी पोषण स्थिति में सुधार के लिए हस्तक्षेप प्रदान करने पर भी ध्यान केंद्रित करेगी।

पीएम पोषण योजना भारत में बच्चों की पोषण स्थिति को बेहतर बनाने के लिए सरकार के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना संभावित रूप से लाखों बच्चों तक पहुँच सकती है और उनके स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार कर सकती है।



पीएम पोषण योजना का विवरण इस प्रकार है

यह योजना 2021-22 से 2025-26 तक पांच वर्षों के लिए क्रियान्वित की जाएगी।

इस योजना का कुल बजट 54,061.73 करोड़ रुपये है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारें 31,733.17 करोड़ रुपये का योगदान देंगी। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 22,328.56 करोड़ रुपये का योगदान देंगे।

इस योजना में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले 6-14 वर्ष की आयु के सभी बच्चे शामिल होंगे।

इस योजना के तहत बच्चों को पका हुआ भोजन, नाश्ता और दूध उपलब्ध कराया जाएगा।

इस योजना का ध्यान भोजन तैयार करने और वितरण की गुणवत्ता में सुधार लाने पर भी होगा।

यह योजना बच्चों की पोषण स्थिति की निगरानी करेगी तथा उनकी पोषण स्थिति में सुधार के लिए हस्तक्षेप करेगी।

पीएम पोषण योजना भारत में बच्चों की पोषण स्थिति को बेहतर बनाने के लिए सरकार के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना संभावित रूप से लाखों बच्चों तक पहुँच सकती है और उनके स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार कर सकती है।<sup>14</sup>

मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का उद्देश्य

सरकारी स्कूलों, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, शिक्षा गारंटी योजना (ईजीएस) केंद्रों, वैकल्पिक और अभिनव शिक्षा (एआईई) केंद्रों और स्थानीय रूप से वित्त पोषित स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार करना।

सामाजिक-आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को नियमित रूप से स्कूल आने के लिए प्रेरित करना और उन्हें कक्षा की गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करना।

गर्मी की छुट्टियों के दौरान सूखा प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिक स्तर के बच्चों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना। यह कार्यक्रम दो महत्वपूर्ण सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के साथ सीधे जुड़ा हुआ है। एसडीजी 2- भुखमरी को समाप्त करना और एसडीजी 4 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देना।

भूख और कुपोषण समाप्त करना, स्कूल में नामांकन और उपस्थिति में वृद्धि जातियों के बीच समाजीकरण में सुधार, विशेष रूप से महिलाओं को जमीनी स्तर पर रोजगार प्रदान करना।<sup>15</sup>

गुणवत्ता की जाँच

एगमार्क गुणवत्ता वाली वस्तुओं की खरीद के साथ ही स्कूल प्रबंधन समिति के दो या तीन वयस्क सदस्यों द्वारा भोजन का स्वाद चखा जाता है।

खाद्य सुरक्षा

यदि खाद्यान्न की अनुपलब्धता या किसी अन्य कारण से किसी भी दिन स्कूल में मध्याह्न भोजन उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो राज्य सरकार अगले महीने की 15 तारीख तक खाद्य सुरक्षा भत्ता का भुगतान करेगी।

विनियमन

राज्य संचालन - सह निगरानी समिति (SSMC) पोषण मानकों और भोजन की गुणवत्ता के रखरखाव के लिये एक तंत्र की स्थापना सहित योजना के कार्यान्वयन की देखरेख करती है।



पोषण स्तर - प्राथमिक (1-4 वर्ग) के लिये 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन तथा उच्च प्राथमिक (6-8 वर्ग) के लिये 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन के पोषण मानकों वाला पका हुआ भोजन।<sup>6</sup>

साहित्य का पुनरावलोकन

देवघर के अनुसार (2007) - अपने शोध पत्र में बताया है कि प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों का इस्तेमाल किया है। इन्होंने स्कूलों और रसोई में स्वच्छता और साफ सफाई के मानकों पर शोध प्रस्तुत किया है। इन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि भोजन मध्याह्न योजना के अंतर्गत साफ-सफाई का विशेष ध्यान नहीं रखा जा रहा है।

श्रीनिवासन के अनुसार (2010) - श्रीनिवासन ने प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों का प्रयोग किया है। उनके शोध के अनुसार मध्याह्न भोजन व्यवस्था स्कूलों में भुखमरी तथा बच्चों में पोषण के स्तर को सुधारना गरीब बच्चों के लिए विद्यालय जाने के लिए प्रेरित करना तथा उनकी उपस्थिति की दर को बढ़ाने में मदद करना रहा है तथा इन्होंने यह निष्कर्ष निकला है कि मध्याह्न भोजन व्यवस्था से स्कूलों में भुखमरी तथा बच्चों में पोषण के स्तर में सुधार नहीं हुआ है।

प्रदीप गिरी के अनुसार (2011) - प्रदीप गिरी ने अपने शोध में बताया कि मध्याह्न भोजन योजना के प्रति अभिभावकों तथा अध्यापकों की दृष्टिकोण का अध्ययन किया तथा मध्याह्न भोजन योजना के जरिए शैक्षिक स्तर का अध्ययन किया और इन्होंने एक सकारात्मक व सापेक्ष मध्याह्न भोजन योजना को विकसित करने का सुझाव दिया।

दत्ता के अनुसार (2015) - स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना के राष्ट्रीय कार्यक्रम (मिड डे

मील) प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के उद्देश्य के साथ नवंबर 1995 के बाद राज्य में लागू करने के तहत किया गया है। उपस्थित बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार तथा बच्चों के सीखने के स्तर में सुधार एवं बच्चों का पोषण प्राप्त होगा।<sup>7</sup>

मध्याह्न भोजन योजना (मिड-डे मील योजना) भारत में बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। इसका प्रभाव निम्नलिखित है -

शिक्षा पर प्रभाव

1 उपस्थिति में सुधार - मिड-डे मील योजना से स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति दर में वृद्धि होती है। यह खासकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को नियमित रूप से स्कूल आने के लिए प्रेरित करती है।

2 ड्रॉपआउट दर में कमी - इस योजना के कारण स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में कमी आई है। भोजन मिलने से बच्चों का स्कूल में बने रहना आसान हो जाता है।

3 शैक्षिक प्रदर्शन में सुधार - पौष्टिक भोजन मिलने से बच्चों की मानसिक और शारीरिक क्षमता में सुधार होता है, जिससे वे पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं।

स्वास्थ्य पर प्रभाव

1 पोषण में सुधार- मिड-डे मील योजना के तहत बच्चों को पौष्टिक भोजन मिलता है, जो उनके समग्र विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति करता है।

2 बीमारियों की कमी - नियमित और संतुलित भोजन मिलने से बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है जिससे वे कम बीमार पड़ते हैं।



3 विकास में सहायता - पौष्टिक भोजन बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे उनकी वृद्धि और विकास में सुधार होता है।

मध्याह्न भोजन योजना न केवल बच्चों की शैक्षिक उपलब्धियों को बढ़ावा देती है, बल्कि उनके स्वास्थ्य में भी सकारात्मक परिवर्तन लाती है, जिससे उनका समग्र विकास सुनिश्चित होता है।<sup>8</sup>

### चुनौतियों का सामना

मध्याह्न भोजन योजना के क्रियान्वयन में कई चुनौतियां हैं। कुछ प्रमुख चुनौतियां इस प्रकार हैं -

- इस कार्यक्रम की सफलता के बावजूद, भारत में बाल भूख एक समस्या के रूप में बनी हुई है।
- कुछ विद्यालयों में लकड़ी से भोजन बनाया जाता है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि होती है।
- कुछ विद्यालयों में मध्याह्न भोजन तैयार करने के लिए उचित रसोई और भंडार कक्ष की सुविधा नहीं है।
- गुणवत्ता और स्वच्छता मानकों को बनाए रखना।
- कुछ ऐसे उदाहरण भी हैं, जहां बच्चे केवल भोजन के लिए स्कूल आते हैं और खाने के तुरंत बाद चले जाते हैं।
- योजना का मुख्य फोकस भोजन की पहुंच पर है, ना कि भोजन की मात्रा या गुणवत्ता पर।
- मिड डे मील पर की कैग की परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट में ना केवल शिक्षा मंत्रालय द्वारा वित्तीय कुप्रबंधन पाया गया, बल्कि यह भी पता चला है कि इस योजना के लिए निर्धारित

123.29 करोड़ रुपये के फंड के डायवर्जन में राज्यों की भी संलिप्तता थी।

➤ कुछ जगहों पर उच्च जाति के बच्चे, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की महिलाओं द्वारा पकाए गए भोजन को खाने से मना कर देते हैं, कुछ जगहों पर दलित और पिछड़े वर्ग के छात्रों को दूसरों से अलग बिठाया जाता है।

➤ योजना का कार्यान्वयन दोषपूर्ण है, उचित दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया जाता, चाहे वह खाने का मेन्यू हो या फिर कैलोरी की मात्रा।

➤ योजना से संबंधित अन्य प्रमुख चुनौतियों में अनियमितता, भ्रष्टाचार, स्वच्छता, अपर्याप्त पोषण सामग्री आदि शामिल हैं।

➤ इसके अतिरिक्त, कभी-कभी कुप्रबंधन, चोरी और खाद्य संदूषण की घटनाएं भी सामने आती रहती हैं, जो बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं।<sup>9</sup>

मध्याह्न भोजन योजना (पीएम पोषण योजना) और शिक्षा को सफल बनाने के लिए सुझाव :

- बेहतर सुविधाओं के लिए, सार्वजनिक निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- कॉरपोरेट्स की मदद लेना एक आसान तरीका है।
- एमडीएम में भ्रष्टाचार को कम करने और जवाबदेही बढ़ाने के लिए सामुदायिक निगरानी, सामाजिक लेखा परीक्षा, विकेंद्रीकृत शिकायत निवारण प्रणाली, लाभार्थियों और मेन्यू आदि पर जानकारी का सार्वजनिक प्रदर्शन किया जाना चाहिये।
- शिक्षकों को मध्याह्न भोजन योजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी नहीं सौंपी जानी



चाहिए, क्योंकि इससे शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में बाधा आती है।

- रसोइयों को अच्छा वेतन मिलना चाहिए, ताकि वे रुचि और प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर सकें।
- मध्याह्न भोजन तैयार करने के लिए एलपीजी, किचन और स्टोर रूम की उचित व्यवस्था होनी चाहिए।
- स्कूलों को समय पर धन और अच्छे अनाज का हस्तांतरण सुनिश्चित किया जाना चाहिये।
- खाद्यान्नों और पके हुए भोजन की गुणवत्ता की नियमित रूप से जांच की जानी चाहिए और गुणवत्ता संबंधी सभी शिकायतों का तत्काल समाधान किया जाना चाहिए।<sup>10</sup>

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इन चुनौतियों के समाधान के लिए सरकारी अधिकारियों, स्कूल प्रशासन, समुदाय के सदस्यों और नागरिक समाज संगठनों को शामिल करते हुए बहु हितधारक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। निरंतर मूल्यांकन, फीडबैक तंत्र और सहयोगात्मक प्रयास इन चुनौतियों को दूर करने और मध्याह्न भोजन मिड-डे मील योजना के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं।

## निष्कर्ष

हम इस अध्ययन में निष्कर्ष रूप से कह सकते हैं कि मध्याह्न भोजन योजना से छात्रों और अभिभावकों को कई लाभ मिलते हैं। सबसे पहले, यह माता-पिता को अपने बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करती है, क्योंकि उन्हें हर दिन कम से कम एक पौष्टिक भोजन मिलने का आश्वासन दिया जाता है। यह योजना कुपोषण को कम करने और बच्चों के समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में भी मदद करती है, जिससे बेहतर संज्ञानात्मक विकास और शैक्षणिक प्रदर्शन होता है। माता-पिता के लिए,

यह योजना उनके बच्चों को भोजन उपलब्ध कराने के वित्तीय बोझ को कम करती है, खासकर आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे परिवारों के लिए।

अंततः कहने का तात्पर्य है कि कुछ मामलों में भ्रष्टाचार हो सकता है, लेकिन मध्याह्न भोजन योजना (मिड-डे मील योजना) ने देश भर में प्राथमिक कक्षाओं में लाखों बच्चों को भोजन उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उनकी पोषण स्थिति और स्कूल में उपस्थिति में उल्लेखनीय सुधार किया है। भ्रष्टाचार को दूर करने और कम करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास जारी हैं कि योजना कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से संचालित हो।

इसलिए हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में मध्याह्न भोजन योजना (पीएम पोषण योजना) और शिक्षा का प्रभाव न केवल बच्चों की शैक्षिक उपलब्धियों को बढ़ावा देती है, बल्कि उनके स्वास्थ्य में भी सकारात्मक परिवर्तन लाती है, जिससे उनका समग्र विकास सुनिश्चित होता है।

## संदर्भ ग्रन्थ

- 1 विकासपीडिया, इन/एजुकेशन/पॉलिसीज, मध्याह्न भोजन योजना (मिड डे मील)।
- 2 विकिपीडिया, मध्याह्न भोजन योजना (दोपहर के भोजन की योजना)।
- 3 दृष्टि द विजन, मध्याह्न भोजन योजना (पीएम पोषण योजना), 3 अक्टूबर, 2022।
- 4 [www.educationforallindia.com/mid-day-meal-scheme-2023/](http://www.educationforallindia.com/mid-day-meal-scheme-2023/)
- 5 अक्षयपत्र, ओआरजी.कॉम
- 6 दृष्टि द विजन, मध्याह्न भोजन योजना (पीएम पोषण योजना), 3 अक्टूबर, 2022
- 7 खान, मोहम्मद इसरार एवं मौर्या, सोनम (2016) 'मध्याह्न भोजन व्यवस्था का बच्चों की शिक्षा व



# शब्द-ब्रह्म

भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका

E ISSN 2320 – 0871

17 जुलाई 2024

पीअर रीव्यूड रेफ्रीड रिसर्च जर्नल

---

स्वास्थ्य पर प्रभाव (विकास खण्ड बहेड़ी जनपद बरेली  
के विशेष संदर्भ में), इंटरनेशनल जर्नल ऑफ अपलाइड  
रिसर्च

8 आहु जा राम (2016), 'सामाजिक समस्याएं', रावत  
पब्लिकेशन्स, जयपुर, पृष्ठ 255-256

9 [www.sanskritias.com/Mid-Day Meal  
Scheme](http://www.sanskritias.com/Mid-Day Meal Scheme)

10 [www.educationforallinindia.com/mid-day-  
meal-scheme-2023/](http://www.educationforallinindia.com/mid-day-meal-scheme-2023/)

---